

प्रधान का इस्तीफा, केस वापसी, मुआवजा, सरकार ने मानी सभी मांगें, सीजेपी ने खत्म किया आन्दोलन

नई दिल्ली (आम)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे के बाद सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच में बैकवर्ड हुई। इसमें सरकार ने उनकी बाकी दो मांगों को भी मान लिया है। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने आरोपन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के ऐलान के बाद उत्तर भारत पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमन का माहौल है। कॉलेजों जमना पार्टी के



कांकर अमीजित दीपके ने इसे छात्रों की जीत बताया। उन्होंने मंच से इसका

थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस सरकार में मंत्री इस्तीफे नहीं देते। लेकिन हमने कर दिया। हमने आखिरकार कर दिया। धर्मन प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आज में उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि झुकती है दुनिया झुकने वाला चाहे। भाजपा सांसद धर्मन प्रधान के मंत्री पद से दिए इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। यह पिछले तीन दिनों में मंत्री सरकार के दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे

पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रवीन्द्र सिंह बिंदु ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कांग्रेसक जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी माहौल को नॉर्मल करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर के आसपास के हिस्सों में इंटरेक्ट कर से बहाल कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आंदोलन में हिता को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पर भी निशाना

साधा। उन्होंने छात्रों के साथ हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हमारे लिए यह एक बुनियादी मुद्दा है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी अपनी ही फोर्स भारत के मंत्रियों पर गोली चलाए। संसद में

दिया था। उन्होंने ही हमारे छात्रों के खिलाफ पोलिट गन समेत धातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हमारे लिए यह एक बुनियादी मुद्दा है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी अपनी ही फोर्स भारत के मंत्रियों पर गोली चलाए। संसद में

यह एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह आंदोलन भारतीय छात्रों की और से सरकार को एक चेतावनी है। छात्रों ने बतावनी दी है कि आप आप भारत को उस तरह नहीं चला सकते जैसे अब तक चलाते रहे हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर: निकाला विजय जुलूस, बांटी मिठाई

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस प्रचारियों, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एक हल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित था। के प्रथम प्रशासनीय प. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीद अमन भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाँटकर खुशियों को साझा किया।



—छात्रों की एकजुटता को मिली जीत— विश्वनाथ

कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि सच्चे आर्थी में एक देश के युवाओं की जीत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस्तीफा प्रधान को त्याग पत्र देना ही होगा और उनकी बात फिर सच्य सिद्ध हुई। सहा कि जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शहा सीधे जिम्मेदार हैं। छात्रों पर चलाई गई पोलिट गन बलादी गई। देश से माफी मांगनी चाहिये।

वाहिद अली सिद्दीकी, संदीप श्रीवास्तव, अलीम अख्तर, कर्नल ए. के. सिंह, नंदेश्वर शुक्ल ने कहा कि प्रथममंत्री नरेन्द्र मोदी को युवाओं से माफी मांगनी होगी। ये भारत के अंतरि है और अतीत की भीषण से लड़ नहीं सकता। कहा कि सच्चे आर्थी में यह लोकतंत्र की जीत है। युवाओं की मांगों को पूरा करना ही होगा।

विजय जुलूस में मुख्य रूप से जयंत चौधरी, डा दीपनंद सिंह, अमित सिंह सुरेंद्र मिश्रा, रफीक खान, नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ

बस्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस प्रचारियों, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एक हल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित था। के प्रथम प्रशासनीय प. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीद अमन भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाँटकर खुशियों को साझा किया।

बस्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस प्रचारियों, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एक हल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित था। के प्रथम प्रशासनीय प. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीद अमन भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाँटकर खुशियों को साझा किया।

बस्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस प्रचारियों, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एक हल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित था। के प्रथम प्रशासनीय प. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीद अमन भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाँटकर खुशियों को साझा किया।

बस्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस प्रचारियों, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एक हल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित था। के प्रथम प्रशासनीय प. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीद अमन भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाँटकर खुशियों को साझा किया।

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कोतावली थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार युवक से छह लाख रुपये दान का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाबू के खिलाफ 6 गैरवांछनीय और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिलागिनी थाना पुलिस कुमार शुक्ल पुत्र कुश प्रकाश शुक्ल ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बेरोजगार और उनकी मुलाकात बेरोजगार शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बाबू के पद पर तैनात मिश्र नाम के व्यक्ति से हुई। आरोप है कि मिश्रजी ने खुद को एक लोको शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने वाला बताते हुए शिक्षायातकता

से अरारह लाख रुपये की मांग की, जिससे से छह लाख रुपये पहले देने की शर्त रखी गई। शिक्षायातकता के अनुसार, उन्होंने रिक्तेदारों व हितियों से रुपया का इस्तेमाल कर 18 नवम्बर 2018 को दो गैरवांछनीय नौकरी में बेरोजगार शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आरोपी को छह लाख रुपये तक दे दिए। इसके बाद भी नौ नौकरी लगी आज भी रुपय वापस नहीं। आरोपी टाटमोटीकर सहा और कादरपुर पर सैकड़ों संदेश भेजकर आतंक फैला रहा।

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय में बाबू के खिलाफ दर्ज

15 वीं पुण्य तिथि पर रक्तदान, संगोष्ठी, सहभोज के साथ दाद किये गये विष्णुदत्त ओझा, 166 ने किया रक्तदान

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। जन संस्कारों के प्रति समर्पित विष्णुदत्त ओझा के 15 वीं पुण्य तिथि पर शुनिवार को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुत्रकुलस्थ एवं वामनाल टाउन बस्ती के परिसर में रक्तदान शिबिर 'रक्तदान एक सामाजिक जिम्मेदारी' विषयक संगोष्ठी और सहभोज का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुये विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आस्था के बीच 166 लोगों द्वारा रक्तदान के साथ ही स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये स्मृतियों को साझा किया गया।



मानवता के प्रति सभी स्वस्थ नागरिकों का नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है।

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

रक्तदान शिबिर के दौरान बाबूक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का श्रौतिय शरीर भारी बीच चला है। कि उनका योगदान संदेव याद किया जायेगा। भी सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रचार्य और समाज ओपप्रकाश और, भाग्य चित्त आलोक विकासानी मिश्र, सुनील सिंह, गोपेश्वर त्रिविदी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं, यह

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 26 जुलाई 2026 रविवार

सम्पादकीय

शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान का त्याग पत्र

देश की राजधानी जन्तर मन्तर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कैबिनेट शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधान के इस्तीफे पर जहां कोकचय जनता पार्टी (सीजेपी) खुशी से झूम रही है तो विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत और सरकार के लिए 'पहली हार' करार दिया है। देश को कुछ एप आंदोलनकारी चेहरे मिल गए हैं तो सोशल मीडिया और 'जेंट जी' ने अपनी ताकत के साथ क्रांति के नए तौर-तरीकें भी पेश किए।

धर्मेश प्रधान ने इस्तीफा देते हुए एक खुला खत भी देश के युवाओं के नाम लिखा। इसमें उन्होंने जन्तर-मन्तर पर चल रहे आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर उनका मन दुखी था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का विषय नहीं। भारत की युवा शक्ति को देश की असली ताकत बताते हुए प्रधान ने कहा, 'जन्तर-मन्तर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विशेषी ताकतें ताम ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का मविष्य कानूनी पेशीवर्गियों ने ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें इसी बात पर धियार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र नम्रान प्रणयनमंत्री जी को भेज दिया है।

कहा जा रहा है कि प्रधान सरकार के 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता के आक्रोश की वजह से किसी मंत्री को इस तरह कुर्सी छोड़ना पड़ा है। हालांकि, इससे पहले सोशल मीडिया पर चले 'भौदू' आंदोलन के समय अक्टूबर 2018 में एमजे अखतर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन उनको इस्तीफे के लिए सरकार पर इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। कोकचय जनता पार्टी की ओर से 20 जून को शुरू किए गए आंदोलन शुरूआत में मले ही मीड जुटाने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन 18 जून को सौरमा वांग्कुकर को जन्तर-मन्तर में प्या उठायी गया, आंदोलन ही उठ खड़ा हुआ। 7 दिनों में सित तह आंदोलन के प्रति युवाओं में समर्थन उमड़ा उसने पूरी तस्वीर बदल दी। सरकार ऐसे दौरेाह पर खड़ी थी जहां एफ तरफ उसकी प्रतिक्रिया दांव पर थी, तो दूसरी तरफ देश के वो युवा, जिन्हें बहुत नाराज करने का जोशिम लेना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था।

ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह मोदी सरकार की हार है? कांग्रेस, आन आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उदभव ठाकरे) जैसे दलों ने इसे मोदी सरकार की हार करार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे सरकार की संवेदनशीलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि, सवाल यह भी उठता है कि सरकार को युवाओं की आवाज सुनने में इतना वक्त क्यों लगा?

माना जा रहा है कि सरकार ने काफी सोच और विचार-विमर्श के बाद प्रधान का इस्तीफा लिया है। असल में यह मोदी सरकार के लिए तात्कालिक घटनाक्रम जरूर है, लेकिन राजनीति में अक्सर फैसले दूरगामी नीतियों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। समझा जा रहा है कि मोदी सरकार ने ऐसे ही नफा-नुकसान को तोलकर यह फैसला लिया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश संसत पांच रातों में चुनाव है। ऐसे में युवाओं की नाराजगी को बढ़ावा नहीं दिया जा बाल्या जा रहा है कि सरकार ने युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार उनको आवाज को सुनती है और उनके मविष्य को लेकर कठोर फैसले करने से नहीं करारएगी।

माना जा रहा है कि सरकार ने धर्मेश प्रधान का इस्तीफा लेकर संसद को सुचारु रूप से चलाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 'पहले इस्तीफा फिर चर्चा' की मांग पर गड गई थी। सरकार इसी सत्र में पेपर लीक के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। इससे अगला शुक्रवार को कीर्तित्व ने एक कि. प्याक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें प्रमनत्र लीक के लिए 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। सरकार की कोशिश अपनी छवि बदलकर युवाओं को इसी तरह मानाया से जोड़ना होगी, जिनके सन पर यह पिछले डेढ़ दशक में एक के बाद एक चुनार्यों में जीत हासिल करती रही है।

मौजूदा घटनाक्रम का विष्णा कितना फायदा उठा पाएगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। वर्षों से विष्णा का विरोध सोशल मीडिया तक सीमित हो गया था, लेकिन नाराज के आंदोलन के बाद ही सही लेकिन जिस तरह कई विपक्षी दलों ने सड़कों को उतरकर संघर्ष किया, उसने उनके कांडर में एक नया जोड़कर उत्तर जगा दिया। मई की शुरूआत तक जित अभिजित दीपक का नाम देश के लोगों ने सुना नहीं था और जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में जुटे थे, यह युवाओं के नए नायक के तौर पर उभरे हैं। वहीं, 26 दिनों तक अनगरा करके सामाजिक कार्यकर्ता सौरमा वांग्कुकर ने गांधीवादी आंदोलनकारी के रूप में अपनी राइडर पहचान हासिल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंदोलनकारी मविष्य में किन और मुद्दों को उठावेंगे।

इस सरकार में यह लोक लाज का पहला उदाहरण है कि जनता के दबाव में ही सही और विष्णा के दबाव में ही सही, सरकार ने इस मुद्दे को मान्यता प्रदान का इस्तीफा हुआ। अतः किसान आंदोलन के दबाव में कानून वापस होना, तो वो भी त्याग योग्य है। यह सरकार की हार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जीत है। अब ऐसे साम्प्रान निकले की पुनरूपूक व्यवस्था बने। सरकार को विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए और उनकी सिफारिशों पर काम करना चाहिए। सरकार और विपक्ष इसे अब नाक का सवाल न बनाए। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना जरूरी होता है। सरकार ने इस बात को माना। बात सिर्फ नौट परीक्षा की नहीं है। पहले भी ऐसे मामला हुए। सरकार पहले मान करती रही, फिर री-वीकर करती रही। देशभर में एक लाख से ज्यादा सरकारी छात्रों बंद हो गए। ये सब भी बड़े मुद्दे हैं। अख्श हो कि सरकार युवाओं, छात्रों की भावनाओं को समझे और समस्याओं का प्रमावी हल निकाले। इसे हार-जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हासिल



— डॉ. सत्यवान सौरभ—

भारत की शिक्षा व्यवस्था आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक मंत्रालय तक सीमित नहीं है। यह एक बहुतरासी संकट है, जिसमें नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयन की कमी, संसाधनों की कमी, शिक्षक-प्रशिक्षण की चुनौती, परीक्षा-केंद्रित संघ और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ एक साथ मौजूद हैं। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो इसका उत्तर केवल राजनीति नहीं, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक ही होना चाहिए। सच यह है कि केवल मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था अपने-आप नहीं सुधरती सुधर चुका तब होता है जब नीति, नीतिव, निवेश और निष्पान, बांसे एक दिशा में काम करें।

भारत में शिक्षा को लंबे समय से 'नीति' से अधिक 'घोषणा' के स्तर पर देखा गया है। हर सरकार शिक्षा की बात करती है, लेकिन जमीन पर परिवर्तन की गति बहुत ञ्ी रहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का दावा किया थाकृमना शिक्षा, मतुभाषा-अक्षरित, प्रशिक्षण शिक्षा, कौशल-आधारित, बहुविध अध्ययन, डिजिटल लर्निंग और शोध-उन्मुख उच्च शिक्षा। कामज पर यह नीति अत्यंत महत्वाकांक्षी है। परंतु मलत्वाकंक्षा और प्रमावी क्रियान्वयन के बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर रह जाता



है। यही यह अंतर है, जहां किसी भी शिक्षा मंत्री की असली परीक्षा होती है।

धर्मेश प्रधान के कार्यकाल को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने, बहुभाषी शिक्षा पर बल देने, कौशल विकास को प्राथमिकता देने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने और उच्च शिक्षा को अधिक लचीला बनाने की दिशा में काम किया। यह कहना गलत होगा कि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बहुत-सी योजनाएं आगे बढ़ीं, संवाद बढ़ा, और शिक्षा पर राष्ट्रीय बहस तेज हुई। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याएं जिस की तस बनी रही। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता का अंतर, ग्रामीण-शहरी असमानता, शिक्षकों की कमी, परीक्षा-प्रधान संस्कृति, और कोचिंग-निर्भरता ये सभी समस्याएं अब भी गहरी हैं।

इसी संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा मंत्री की भूमिका क्या होती है। शिक्षा मंत्री न तो अकेले स्कूलों की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, न ही विद्यार्थियों की शोध-भ्रमता बढ़ा सकता है, और न ही एक झटके में करोड़ों विद्यालयों की सीखने की स्थिति बदल सकता है। उसकी भूमिका मुख्यात नीति-निर्माण, समन्वय, बजट प्राथमिकता, संस्थागत निगरानी और राज्यों के साथ सहयोग की होती है। यदि ये जॉबो काम बेहतर हों, तो

शिक्षा में सुधार की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि केवल चेहरा बदल दिया जाए और नीतिगत ढांचा बही रहे, तो परिणाम सीमित ही रहेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बावरी की भांसी नहीं दे पाती। एक ओर महानगरों के निजी स्कूल और महेगे संस्थाएं हैं, जहां सुविधाएं और अस्सर अपेक्षाकृत अधिक हैं, दूसरी ओर सरकारी स्कूल और दूरस्थ ग्रामीण इलाक़े हैं, जहां बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और डिजिटल संसाधनों की भारी कमी है। इस असमानता को कोई एक मंत्री, चाहे वह धर्मेश प्रधान हों या कोई और, अकेले समाप्त नहीं कर सकता। बदले लिए लंबे समय तक चलने वाली राज्य-नीति, केंद्रे-राज्य समन्वय और सामाजिक निवेश की आवश्यकता होती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा सुधार का प्रश्न सिर्फ मलत्वाकंक्षी नहीं, वैचारिक भी है। दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा पास करने वाली मशीन के रूप में देखी जाती रही है, कि सौच विकसित करने वाले माध्यम के रूप में। रतत शिक्षा में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमता को सीमित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है, लेकिन बदलाव केवल दस्तावेजों में ही रह गया। इसके लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षक-प्रशिक्षण और

कक्षा-स्तरीय व्यवहार में परिवर्तन चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सुधारों का वास्तविक परीक्षण होता है।

धर्मेश प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वालों का तर्क यह हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन से जवाबदेही बढ़ती है और नई ऊर्जा आती है। यह तर्क आंशिक रूप से सही भी है। किसी भी मंत्रालय में नेतृत्व की शैली, प्राथमिकताएं और कार्य-संस्कृति महत्वापूर्ण होती है। यदि किसी मंत्री के कार्यकाल में संवाद कमीजों हों, नीतियों के परिणाम धीमे हों, या जमीनी स्तर की शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान न दिया जाए, तो बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है। लेकिन यहीं भी प्रश्न यह है कि क्या बदलाव व्यक्ति में चाहिए या व्यवस्था में। यदि सिस्टम ही कमीजों को, तो नया मंत्री भी उसी ढांचे में काम करेगा। इसलिए इस्तीफा केवल राजनीतिक प्रतीक बन सकता है, समाधान नहीं।

सच यह है कि शिक्षा सुधार की असली कुजी बजट और क्रियान्वयन में छिपी है। भारत की शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश लंबे समय से अपेक्षाकृत कम रहा है। कई बार घोषणाएं बड़ी होती हैं, लेकिन विद्यालयों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं की ख़ाफना, पुस्तकालयों का विकास, छात्रवृत्तियोग, शिक्षक नियुक्तियों और डिजिटल पहुँच जैसे मूलभूत मुद्दे पीछे रह जाते हैं। यदि सरकार शिक्षा को वास्तव में प्राथमिकता देना चाहती है, तो उसे केवल नीति

दस्तावेज नहीं, बल्कि वित्तीय प्रतिबद्धता भी बढ़ानी होगी। शिक्षा वह क्षेत्र है, जहां खर्च को बोझ नहीं, निवेश मानना चाहिए।

शिक्षा इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन भारत में शिक्षकों की स्थिति खुद संकटग्रस्त है। कई स्कूलों में शिक्षक-रिक्तियाँ हैं, कई जगह एक शिक्षक पर अनेक कक्षाओं का बोझ है, और कई संस्थानों में शिक्षक-प्रशिक्षण पुराना और अप्रासंगिक है। जब तक शिक्षक स्वस्थ, सम्मानित और प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई भी शिक्षा सुधार सीमित रहेगा। मंत्री बदलने से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए सेंना-शाली में सुधार, प्रशिक्षण में गुणवत्ता, और शिक्षकों पेशे को प्रोत्साहित देने की जरूरत है।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी सीमाएँ भी समाने आईं। महामारी के दौरान डिजिटल लर्निंग की उपयोगिता स्पष्ट हुई, पर यह भी उजागर हुआ कि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट, उपकरण और डिजिटल साधनों की भारी कमी है। अब डिजिटल शिक्षा को केवल गैरट आधारित नीति नहीं, बल्कि समग्र नीति बनाना होगा। इसका अर्थ हैक गुणवत्ता के दोरान अत्यंत ठेक गुणवत्ता के कारण लगत वाले उपकरण, स्थायी माध्यामों में समायी, और शिक्षकों को तकनीक के लिए तैयार करना। केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देने से शिक्षा अभ्युक्ति नहीं हो जाती।

उच्च शिक्षा की बात करें तो भारत में शोध, नवाचार और आधुनिक तकनीक अमी भी कई चुनौतियाँ से पीछे है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पुराना पड़ जाता है, शोध-फंड सीमित रहता है, और प्रशिक्षण हासिल करने में अनेक बाधाएँ होती हैं। यदि शिक्षा मंत्री बदलने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, अनुकूलता का वातावरण, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सुधार आती है, तभी उम्मीदों का वास्तविक अर्थ होगा। अतः केवल राजनीतिक बयानबाजी से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। यह भी आवश्यक है कि हम

शिक्षा सुधार को चुनावी बहस की तरह न देखें। शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका परिणाम अगले दिन नहीं दिखता। किसी भी सरकार के लिए यह आसान होता है कि वह नई नीति की घोषणा कर दे, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे दस साल तक निरंतर लागू करें। यही निरंतरता सबसे महत्वापूर्ण है। यदि हर मंत्री पिछली नीति को पूरी तरह बदलने लगे, तो शिक्षा व्यवस्था स्थिर नहीं रहे पाएगी। इसलिए सही प्रश्न यह नहीं है कि धर्मेश प्रधान जाँए या रहे, सही प्रश्न यह है कि क्या कोई भी नेतृत्व शिक्षा को दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिचोजना की तरह देख रहा है।

भारत के लिए शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार नहीं, नागरिकता भी है। एक शिक्षित समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है, वैचारिक सोच को बढ़ाता है, सामाजिक विभक्तता को चुनौती देता है और महिलाओं तथा विपक्ष समुदायों के लिए नए अवसर खोलता है। इसलिए शिक्षा सुधार को केवल सरकारी विभाग की प्रशासनिक उपलब्धि मानना गलत होगा। यह राई-निर्माण की प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता और सामाजिक सहयोग हैं, तो बदलाव संभव है। वरना नेतृत्व परिवर्तन भी एक औपचारिकता बन न जाया।

अंततः निष्कर्ष साफ है। धर्मेश प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था अपने-आप नहीं सुधरेगी। ही, यदि उनके स्थान पर आने वाला नेतृत्व अधिक संवेदनशील, अधिक जवाबदेह और अधिक परिणाममुख होगा, तो सुधार की गति बेहतर हो सकती है। लेकिन मूल सुधार मंत्री के जाने से नहीं, व्यवस्था के बदलने से आएंगे। भारत की शिक्षा प्रणाली को चाहिएकृ स्थायी नीति, पर्याप्त धन, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल समावेशन, शोध-निर्माण और सामाजिक समानता।

यही ये अक्षा हैं, जिन पर वास्तविक सुधार चले हों सकता है। चेहरा बदलना आसान है व्यवस्था बदलना कठिन। और भारत की शिक्षा व्यवस्था को अब आसान नहीं, कठिन और ईमानदार सुधार की आवश्यकता है।

प्रतिशोध का माध्यम बनते कार्यस्थल



डा. रिंतू सारस्वत

प्रश्न केवल वैवाहिक विवादों की नहीं, बल्कि उस सामाजिक मर्यादा का भी हो ज़्यादा और प्रतिशोध के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखती है। यदि निती सार्वजनिक प्रक्रिया को नष्ट करने का माध्यम बनने लगे, तो यह केवल एक व्यक्ति की पराजित बन जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के एक घिताजक पक्ष पर गंभीर विचार व्यक्त की है। न्यायमूर्ति बी. आ. नागरना एवं न्यायमूर्ति आर. महेदेवन की पीठ ने मौखिक रूप से दिपणी की कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे को शिकायत अथवा बरिष्ट अधिकारियों को शिकायत-पत्र भेजने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों के परिणामस्वरूप कई बार संबंधित व्यक्ति की नौकरी बंद हो जाती है या उसका सेवा-जीवन प्रभु रूप से प्रभावित होता है। न्यायालय के अनुसार, तात्काल का मुकदमा लड़ना एक अलग बात है, किंतु किसी व्यक्ति की आजीविका और पेशेवर प्रतिष्ठा को संकट में डाल देना कहीं अधिक गंभीर है।

यदि किसी व्यक्ति की नौकरी ही समाप्त हो जाए, तो इसका प्रतिकार प्रभाव मरण-पोषण (मैटेनेंस) जैसे वैधानिक दायित्वों की पर बड़ सकता है। पिछले पांच दशकों में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के नियोक्ता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान अथवा मानसिक शिकायतें करना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सेवा-जीवन और



आजीविका पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे अपराध को मानसिक क्रूरता के दृष्टिकोण से परीक्षण किया है तथा परिस्थितियों के अनुसार इसे वैवाहिक संबंध-विच्छेद का आशे भी देखा है। इस संदर्भ में सबसे प्रासंगिक और उल्लेखनीय निर्णयों में से एक 'भुक्तुलता कुमारी बनाम ओम प्रकाश बड़ई' (दिल्ली उच्च न्यायालय, 1980) का है।

इस मामले में अलग यह रही पत्नी ने लोकसभा सभाियालय, जहां उसका पति कार्यरत था, को पत्र लिखकर उस पर दुर्व्यवहार तथा अपमान करने का आरोप लगाया। न्यायालय ने पाया कि यदि पत्नी का उद्देश्य केवल मरण-पोषण प्राप्त करना था, तो उसके लिए यह कहना पर्याप्त था कि उसे मरण-पोषण नहीं मिल रहा है। इसके लिए पति तथा उसके परिवार के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने इस प्रकार की शिकायतों के प्रभाव पर दिपणी करते हुए कहा, 'नियोक्ता के सम्मान इस प्रकार की अस्पष्ट शिकायत के निमित्तसे मानसिक क्रूरता है। इससे कर्मचारी की अपने नियोक्ता की दृष्टि में प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा उसका सेवा-जीवन और पेशेवर्गीय की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायालय ने कहा कि इसका उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसकी मानसिक शांति मन होती है।'

प्रश्न प्रकट इतना नहीं है कि न्यायालयों ने इस प्रकार के अपराध को मानसिक क्रूरता क्यों माना। इससे भी अधिक महत्वापूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत संबंधों में उत्पन्न विवाद किस प्रकार उस सदन तक पहुँच जाते हैं, जहां व्यक्ति न्याय की अक्षम दूतरे को अधिकतम शक्ति प्रदान करता है। जब संघर्ष का उद्देश्य सामाजिक के स्थान

पर दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आजीविका अथवा पेशेवर जिनता को प्रभावित करना बन जाए, तब यह केवल वैवाहिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय संबंधों के नैतिक पतन का भी संकेत देता है। इसी संदर्भ में रॉबर्ट होमन का 'सामाजिक-विवेक्षणिक दृष्टिकोण' महत्वापूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार व्यक्ति केवल अपनी एक पहचान नहीं बनाता, बल्कि समाज भी उसके व्यवहार और कार्य के आधार पर उसके प्रति एक ढांचा विकसित करता है। यही ढांचा समय के साथ बदल सकती सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। इसलिए जब व्यक्तिगत संबंधों का संघर्ष किंवदंती की पेशेवर प्रतिष्ठा को लक्ष्य बनाता है, तो उसका प्रभाव केवल तर्तमान विवाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वर्षों में अजित विवेक्षण और सामाजिक कार्यकार्यता पर भी पड़ता है।

ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी किंवदंता यह होती है कि आरोपी की सत्यता का परीक्षण बहुत बड़ माने होता है, जबकि उनके आधार पर बने वाली सामाजिक कारण ताल्लल अना प्रभाव छोड़ने लगती है। कार्यस्थल पर पहुँचा व्यक्तिगत विवाद व्यक्ति को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है, जहां उसे पत्र घटनाओं को लीर की संकोच, अहजजात और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है जिन्का उसके पेशेवर दायित्वों से कोई संबंध नहीं होता। यह स्थय को अहसास अनुभव करता है, क्योंकि एक ओर न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चल रही रहती है, वहीं दूसरी ओर उसके सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक परिवार उसके बारे में अपनी-अपनी बाधाएँ बनाते लगते हैं। यही कारण है कि ऐसी शिकायतों का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है।

बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी के प्रश्न

—प्रमोद भार्गव—

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बनान और पत्र बायरल हुए हैं, जिसमें बलूच नेता मीर यार बलूच और कूक पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नाम झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलूच आंदोलन उत्साहित हुआ है और ये जवद कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाक सेना ने बलूचिस्तान में फ़ौरतयार कर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के अधिकारी शशासन शाबाज युद्ध कर दिया है। पाक के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजरायली सुक्ष्मिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आर्गनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लड़ाकों के पास से स्टारलिंक उपकरण जब्त किए हैं।

पाक सेना की भी आरोप है कि आगानिस्तान बीएलए को विदेशी बलूचों ने करीब 85 प्रतिशत बलूचिस्तान की भूमि पर काबिजा होने का दावा किया है। बलूच कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अवलि भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन-पाक आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। इसकी सुरक्षा और मविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, जो अर्थिक गैस उपलब्ध है। यही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दायित्वों से कोई संबंध नहीं होता। यह स्थय को अहसास अनुभव करता है, क्योंकि एक ओर न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चल रही रहती है, वहीं दूसरी ओर उसके सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक परिवार उसके बारे में अपनी-अपनी बाधाएँ बनाते लगते हैं। यही कारण है कि ऐसी शिकायतों का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है।



कर दिए थे। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूनवायस खेलने की मांग कर रहे हैं।

प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच बलूच लोगों के अधिकारों की कालांतर के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति स्थापन बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से तारकर बाहर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलूच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत-पाक दोष के बीच 1971 की तरह एक युद्धकालीन घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मरणाए जाने वाले सैनिकों में भारत भी शामिल हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अस्सर अलगाववादी प्रभु प्रधानमंत्री शाहिद खानन अखासी ने भी बलूचिस्तान पर किया है। पाक सेना ने बलूचिस्तान पर सैनिक दखल देना शुरू हो गया। जगह-जगह हथियारों के खंड हवा हुआ। 2020 में एकांक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रशासनों तथा सुखावलियों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकरी नहीं करती है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधन को हड़पने का काम कर रहा है। इसी जगहिए से ग्वादर बंदरगाह को विकासित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंदरों के सम्य बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बढ़ाकर के जोर पर जलविद्युत न केवल कर लिया था। जलविद्युत के स्थय को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं। अतः पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है।

परिणामस्वरूप संघर्षवर्धनी की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में इसतरा विद्रोह खल हो गया था और बीएलए का भी कोई बजुद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद ऐसे तानाशाह जनरल परबज मुख्तार ने नवाज शरीफ का तुराफाल कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाब मिर की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खोरख्मा मिर को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फ़ीनिक्स फ़्ली की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह-जगह हथियारों के खंड हवा हुआ। 2020 में एकांक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रशासनों तथा सुखावलियों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकरी नहीं करती है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधन को हड़पने का काम कर रहा है। इसी जगहिए से ग्वादर बंदरगाह को विकासित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंदरों के सम्य बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बढ़ाकर के जोर पर जलविद्युत न केवल कर लिया था। जलविद्युत के स्थय को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं। अतः पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है।

पांच आधारा के साथ वारिस पंजाब दे का सदस्य जोगा गिरफ्तार

संवाददाता-बहराइच। शनिवार को रुम्हईडीहा थाने की पुलिस ने वारिस पंजाब दे के सक्रिय सदस्य जोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अशोक विभवजी श्रीवास्तव के मुताबिक जोगा सिंह अक्सर घुरपेट करने वाली की मदद कर रहा था। पुलिस ने उसे रुम्हईडीहा से गिरफ्तार करने की बात कही है हालांकि पूरनपुर पीलीभीत में भी दखिब देने पुलिस गई थी। रुम्हईडीहा के एसएसओ हरेंद्र कुमार निष, अपराध निरीक्षक गणेश तिवारी, एसआई सरंज चंद, का सोबिंद यादव ने उसे गिरफ्तार किया है। 66 वर्षीय जोगा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी आयरन एजेंसी, नंदपुर सोनवल्ल चुपियाणा पंजाब का निवासी है। वह इस समय थाना मोनारप जहाँ दूरसंचार इस्तेमाल तथा थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में रह रहा है। पुलिस



के मुताबिक 31 हजार रुपए, पांच आधार कार्ड, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पैन कार्ड व 1 मोबाइल बरामद हुआ है। जोगा सिंह पर थाना मेस्तिगाना जिला होशियारपुर पंजाब में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आयरन एवं विदेशी अतिथियम के अंगत स्थानीय थाने में

मुकदमा दर्ज कर भेज दिया गया है। दर असल मार्ग के अंतिम सप्ताह में जोगा पूरनपुर से पंजाब गया था। हाल में ही वह पूरनपुर आया है। एप्रैल व अन्य खुफिया एजेंसियों को पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली,पीलीभीत में अब इनके स्क्वैड सेल, इनके सुरक्षित छिपने के ठौर

बेटे को ट्रक से बचाने दौड़ी मां भी डंपर की पेट में आई, दोनों की मौत



संवाददाता-गोण्डा। भीषण सड़क हादसे में एक मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मात की मौत के बाद दोनों उनकी तेरहवीं से बापस पर लौटने के लिए सड़क पर खड़े थे। बताया जा रहा है कि कोडिया थाना क्षेत्र के आर्यनगर चौराहा पर मुकवार अंगी हुए हृदय विदारक हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने गोडा बहराइच मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के बसुकिहल लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।

मांमले में मिली जानकारी के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अनिमलपुरा के हरशिम जायसवाल अपने परिवार के साथ कोडिया थाना क्षेत्र कक्षा आर्यनगर चौराहे की रहने वाली अपनी सास सरोज देवी की तेरहवीं में शामिल होने के लिए आए थे। अपनी पत्नी और बेटे के साथ हरशिम तेरहवीं में शामिल हुए और देर रात पर जाने के लिए निकले ही थे कि 11 वर्षीय बेटे लकी को लेकर सड़क किनारे खड़े हुए थे। इसी दौरान बहराइच की तरफ से गोडा जा रहे एक डंपर ने बेटे लकी को रौंद दिया। बेटे को देख जाम मां रीता उर्फ खुशबू बचाने के लिए दौड़ी तो इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे कंटेनर ने उसकी भी रौंद दिया। इससे दोनों की मौत के ही मौत हो गई।

हरिओम जायसवाल के सामने ही 11 वर्षीय बेटे लकी और 30 वर्षीय पत्नी रीता उर्फ खुशबू ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों और

धर्मद्व प्रधान के इस्तीफे से नहीं रुकेगा पेपर लीक -धनंजय सिंह

संवाददाता-गोण्डा। जेलपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि इंदौरा शिक्षा मंत्री धर्मद्व प्रधान का केंद्रीक छात्रों की मांग का सामना है, लेकिन इससे पेपर लीक की समस्या का ब्यापक सामना नहीं होगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से ठोस नीति बनाने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने की मांग की। शनिवार शाम हाल में धनंजय सिंह एक निजी मैरिज हल में आयोजित निजी सिगरेटिटी कम्पनी के निगुडि पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं में होती रही हैं। इससे सहित अधिक नुकसान उन छात्रों का है, जो बच्य तम मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। इनमें किसान, गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चे भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि केवल किसी भी के इस्तीफे से समस्या नहीं हल होगी। जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिससे पेपर लीक की घटनाएं घट न हों। उनके अनुसार, अलग-अलग एजेंसियों

से परीक्षाएं कराने के कारण अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। धनंजय सिंह ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को छात्रों को साथ मिलकर एक सामान परीक्षा व्यवस्था पर विचार करें। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में उन्होंने सीडीएस या एनडीए जैसी संघ परीक्षाओं का पेपर लीक होने की घटना नहीं सुनी। इसलिए सही प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के संवाधान के लिए एक विश्वसनीय एजेंसी तय करने और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विचार होना चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि छात्रों ने लंबे समय तक अलादीन किया, जंतर-मंतर पर धरना दिया और कई कठिनाइयों का सामना किया। सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर उनका सम्मान किया है, जिसके लिए सरकार धवाई की पात्र है। हालांकि अब अलाक पर ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं न हों। उन्होंने केंद्र सरकार से सलत कानून बनाने, शिक्षा विशेषज्ञ और सभी राज्यों के नियुक्तियों के साथ बैठक कर स्थानीय समाधान निकालने की अपील की।

सपा ने फूलन देवी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के आदर्शों को किया याद



संवाददाता-देवरिया। समाजवादी पार्टी ने शनिवार दोपहर दो बजे पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि मनाया। जिला कार्यालय बास देवरिया स्थित मूल्याम सिंह यादव समारोह में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने की, जबकि जिला महासचिव मंजूर हसन ने संबालन किया। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि फूलन देवी का जीवन अनन्या, उन्नीखन और सामाजिक विभ्रमताओं के खिलाफ

संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने शोषित, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, समता और संविधान की मूल भावना के अग्रदूत उनके उनके चित्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने फूलन देवी के संघर्ष और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फूलन देवी ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज बुलंद की। उनका जीवन आज भी लोगों के लिए

प्रेरणामूर्त है। कार्यक्रम के अंत में निजामाबाद के विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आलम बदी के निः पार भी शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो मिम्ट का मौन रखकर विगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप प्रविचार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर अशोक सिंह कुवाहाल, विजय प्रताप यादव, वीरेंद्र साहनी, एडवोकेट जयराम राजभर, डॉ. रामनाथ चौहान, लक्ष्मण निषाद, मोहन गुप्ता, वंदना पारायन, कमलेश राय, रमाकान्त निषाद, राजेंद्र प्रसाद राजेश्वरी, सुनैना सिंह कुवाहाल, लल्लन गुप्ता, हसननाथ यादव, सीमा मौर्य, अशिका चौधरी, राम बबन सिंह यादव, रामजीत यादव, प्रमोद यादव, रविंद्र यादव, इजहारल रक बबलू, अनिल यादव, गोपी यादव, रमेश यादव, हृदयानारायण जायसवाल, निरीश जायसवाल, रणवीर यादव और मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी प्रदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हाइड हाउस की तो तलाश है ही, उन मददगारों की तलाश है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भारत नेपाल की खुली सहद पर छिटपुट जेयन करत हैं। देश में प्रतिबैधित संगठन वारिस पंजाब दे का नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली से निकलकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गया। एप्रैल इस पूरे नेटवर्क को तलाश रही। यूरोपीय व अन्य खुफिया एजेंसियां इसके स्लीपर सेल, संघ हाइड हाउस की नदी आर्थिक रूप से कमजोर उन मददगारों की टोह में डूब गईं। जो इनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। 29 सितम्बर 2021 में पंजाब में वजुद में आए वारिस पंजाब दे के कमांडर इन चीफ अमृत पाल सिंह का विक्रमजीत सिंह दाहिना हाथ माना जा रहा है। उसी की शह

सपा छात्रसभा ने झालमुड़ी बांटेकर मनाया जश्न, धर्मद्व प्रधान के इस्तीफे पर कार्यकर्ताओं में खुशी



संवाददाता-गोण्डा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद्व प्रधान के इस्तीफे के बाद गोडा में समाजवादी छात्र सभा ने शनिवार दोपहर अनेकें अंदाज में जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी तैयार कर उसे पक किया और लोस बहादुर शास्त्री महाविद्यालय चौराहा, गुनू नानक चौराहा तथा अमरहत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआझा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी छात्र सभा ने तीन दिन पहले कलकट गेट पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हीं हिरासत में भी लिया गया था। लगातार चल रहे आंदोलन के दबाव में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा।

शिक्षामित्रों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया ज्ञापन

संवाददाता-कुशीनगर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है। संघ का कहना है कि प्रदेश के हजारों शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के हित में कई आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि, कुछ जिलों में शिक्षामित्रों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रियाएं अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई शिक्षामित्रों को अपने निवास स्थान से 80 से 90 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालयों में संपाद देनी पड़ रही है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री से कई प्रमुख मांगों की हैं।



इनमें शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता प्रमाण (टीईटी/सीटीईटी) में विशेष छूट देकर समायोजन का अवसर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, 11 माह के बचपूरे 12 माह का मानदेय देने और वैरिफ स्कूलों में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में मुख्यमंत्री जन आरंभ योजना के तहत शिक्षामित्रों को नियुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही, सेवा के दौरान

असामयिक निधन होने पर उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता और योग्यता के अनुसार एक सदस्य को राजगार देने की मांग भी प्रमुता है से उठाई गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने कहा कि शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था को नज़रबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उनकी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि शिक्षामित्र समानपूर्यक और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

बार-बैच सेलिया से वादकारियों को मिलना लौटाना न्याय-डीए

संवाददाता-महाराजगंज। कलवट्टे ट बार एस/सिएन महाराजगंज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कलकट्टे समगार में हुआ। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोनगवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ वितरित तथा उन्हें निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी दिखाकर फिर। डीएन के का कह कि बार और बैच के बीच निरंतर संवाद एवं समन्य बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय की उन्मीद लेकर कलकट्टे आने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में निराश होकर वापस न जाए। इसके लिए अधिकारियों और प्रशासन को निष्पक्ष कार्य करना होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेमकाश शुक्ल एडवोकेट ने कहा कि बार के सभी सदस्य वादकारियों के हितों की रक्षा के लिए सर्वेय बैच का संयोग्य करेंगे, ताकि आमजन को सस्ता, सुखम और सम्मन्ध न्याय मिल सके। उन्होंने बार एवं बैच के बेहतर समन्य पर भी जोर दिया।

अयोध्या में पहली बार विराजेंगे विद्वल भगवान



दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मंदिर में चल रही है प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव -भारतीय बस्ती संवाददाता-अयोध्या। श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में पहली बार भगवान श्रीकृष्ण के विद्वल स्वरूप का भव्य मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर की स्थापत्य परंपरा और दक्षिण भारतीय शिल्पकला से निर्मित इस अद्भुत मंदिर में 27 जुलाई को विद्वल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बार दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ तथा पुत्र जिलाधिकारी अनुराध निपाटी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सौजन्य में हुआ, जो 27 जुलाई को भगवान के गमंगह में विजयजानन होने के साथ संपन्न होगा। मंदिर का निर्माण श्रीमद जायदगढ़ रामानुजाचार्य स्वामी राधाचरण जी महाराज के मार्गदर्शन में करारा गया है। लगभग चार वर्षों में तैयार हुए इस मंदिर की स्थापत्य कला, नक्काशी और शिल्प दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों ने साकार किया है। यही कारण है कि यह मंदिर अपनी वास्तुकला और वास्तिक गौरवों के कारण अयोध्या के प्रमुख

आकर्षणों में शामिल होने जा रहा है। महोत्सव के दौरान देव के विभिन्न राव्यों से संत, महंत, धर्माचार्य और वैदिक विद्वान अयोध्या पहुंचेंगे। 27 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भगवान विद्वल के दर्शन सुलभ होगा। (आयोजकों का कहना है कि श्रीराम की नगरी में भगवान विद्वल का यह प्रथम मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का नया केंद्र बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्था के संयोजक रंजेश मिश्रा सरिस्व ने बताया कि मंदिर का प्रत्येक भाग दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुरूप निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी राधाचरण जी महाराज के निर्देशन में चल रहे इस महोत्सव में देशभर से आए संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं का समान भी किया जाएगा। वास्तिक वास्तिक आश्रम की व्यवस्थाओं में रावेंद्र मिश्रा, रश्मि, राजेश मिश्रा, रश्मि तथा उनके सहयोगी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं में 27 जुलाई को विद्वल भगवान के प्रथम दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

गी माता संरक्षण कानून को लेकर 27 जुलाई को निकलेगी शोभायात्रा सीपा जाएगा ज्ञापन

पहुंच गए हवालत संवाददाता-महाराजगंज। कोलुई थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए दो युवकों को रात ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्यवाई करते हुए चालान कर दिया है। विद्वार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवक रात कोलुई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती से मिलने पहुंचे थे। देर रात गांव में बांधूयों को आने की जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोलुई पुलिस दोनों युवकों को थाने ले आई।



पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों युवक गांव की एक लड़की से मिलने आए थे। हालांकि को लेकर गांव में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई थी। पुलिस ने शान्त व्यवस्था बनाए रखने के महानुर दोनो युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्यवाई करते हुए चालान कर दिया। एसओ गौरव सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।

अभियान को युवाओं के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं की भी मरूप समर्थन और संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर दर्शननगर स्थित सूर्यकुंड से 27 जुलाई से कलकट्टे तक भव्य पदयात्रा निकाली जाएगी। गी माता सम्मान आवाहन अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा में छह लाख हस्ताक्षर जिला प्रशासन से 27 जुलाई को शोभायात्रा के साथ छह लाख हस्ताक्षर जिला प्रशासन को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मांग उठाना है। अभियान के अह 40 करोड़ हस्ताक्षर प्रमोद पांडे ने बताया कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से शुरू यह अभियान गी माता के सम्मान और संरक्षण के लिए जनजागरण का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा में चला हज़ार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। मंजू, माझी ने कहा कि

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न



संवाददाता-बहराइच। समाजवादी लाहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया। यह इस्तीफा नीत समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं के सहित आने से चल रहे प्रदर्शन के बाद हुआ है। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे, लाहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेवर यादव ने कहा कि छात्रों और युवाओं की एकता के अंगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर सपा नेता रामजी यादव सहित लोहिया वाहिनी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

संवाददाता-बहराइच। समाजवादी लाहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया। यह इस्तीफा नीत समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं के सहित आने से चल रहे प्रदर्शन के बाद हुआ है। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे, लाहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेवर यादव ने कहा कि छात्रों और युवाओं की एकता के अंगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर सपा नेता रामजी यादव सहित लोहिया वाहिनी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

संवाददाता-बहराइच। समाजवादी लाहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया। यह इस्तीफा नीत समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं के सहित आने से चल रहे प्रदर्शन के बाद हुआ है। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे, लाहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेवर यादव ने कहा कि छात्रों और युवाओं की एकता के अंगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर सपा नेता रामजी यादव सहित लोहिया वाहिनी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

